

न्यूज़ टुडे

भारत के विदेश सचिव के अनुसार भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों की फिर से नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की

हाल ही में संपन्न G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा के प्रधान-मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्व की फिर से पुष्टि की।

- वर्ष 2024 में द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट के बाद भारत-कनाडा संबंध निष्क्रिय हो गए थे। भारत-कनाडा संबंधों के फिर से बहाल होने की दिशा में इसे एक संयमित कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और कनाडा के प्रधान-मंत्रियों की बैठक के अन्य प्रमुख परिणाम:

- दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में साझा रुचि को दोहराया।
- दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में भविष्य में सहयोग करने और व्यापार समझौतों पर फिर से वार्ता शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

भारत-कनाडा संबंधों में हालिया गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक:

- खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा: कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को शरण दी जाती है। भारत इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है।
 - उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 में कनाडा में एक गैर-आधिकारिक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था जिसमें एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र के गठन की मांग की गई थी।
- कूटनीतिक तनाव: कनाडा सरकार ने अपने देश में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय राजनयिकों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।
- सुरक्षा के मामले में सहयोग नहीं मिलना: भारत ने कनाडा में शरण लिए खालिस्तानी आतंकियों के कई बार प्रत्यर्पण की मांग की, परंतु कनाडा सरकार ने इन अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

भारत-कनाडा संबंध

- साझा मूल्य: दोनों देशों के बीच संबंध लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, बढ़ते आर्थिक सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। साथ ही, दोनों देशों के लोगों के बीच भी लंबे समय से विचार-विनिमय होता रहा है।
- आर्थिक संबंध: वर्ष 2023 में भारत से कनाडा को 7.53 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया था। कनाडा से भारत में 5.12 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य का आयात हुआ था।
- वाणिज्यिक और कानूनी सहयोग: दोनों देशों ने 1994 में “पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty)” और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग: दोनों देश ध्रुवीय/ आर्कटिक क्षेत्र में अध्ययन, संचारणीय ईंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।
 - वर्ष 2018 में इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के 100वें प्रक्षेपण से कनाडा के पहले “लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट” का प्रक्षेपण किया था।
- असैन्य परमाणु सहयोग: दोनों देशों के बीच 2010 में परमाणु सहयोग समझौता (NCA) संपन्न हुआ था। यह समझौता 2013 में लागू हुआ था।

ओशन डार्कनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को गंभीर खतरा हो सकता है

यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित हो गया है। यह खासकर आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों में हुआ है।

ओशन डार्कनिंग क्या है?

- ग्लोबल ओशन डार्कनिंग या समुद्र के अंधकारमय का अर्थ है वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक ज़ोन (सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र) सिकुड़ता जा रहा है।
 - फोटिक ज़ोन समुद्री सतह की एक परत होती है। यह लगभग 200 मीटर गहरी होती है। इसमें कुल समुद्री जीवन का लगभग 90% हिस्सा पाया जाता है।

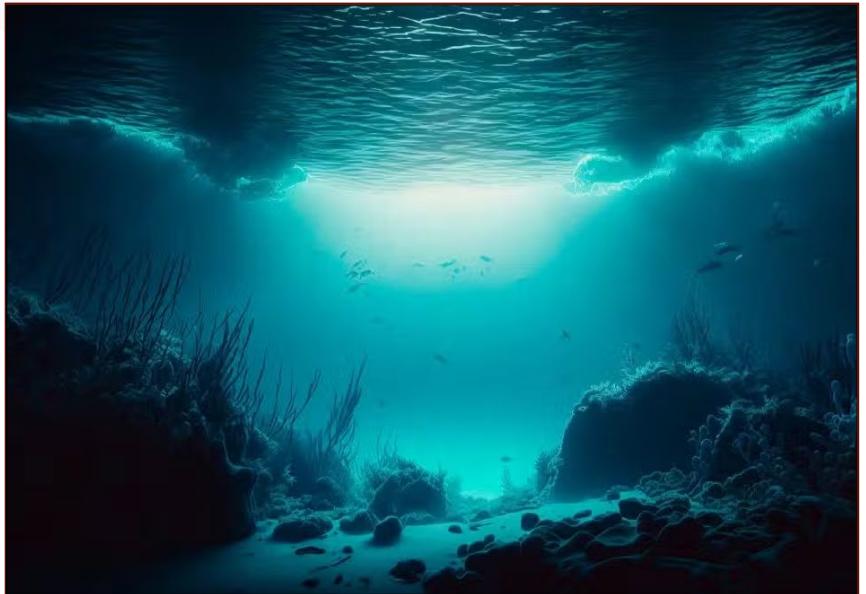
- अध्ययन के अनुसार यह अंधकार संभवतः फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन (सूक्ष्म समुद्री जीवों) की अधिकता के कारण पारिस्थितिकीय बदलाव की वजह से हो सकता है।

ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक

- तटीय महासागरों में: कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट का जमाव हो जाता है जो बहकर समुद्र में चले जाते हैं तथा सूर्य के प्रकाश को निचली परतों में जाने से रोकते हैं।
- खुले महासागरों में: समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन की घटना और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल के परिसंचरण में हुए बदलाव ने खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग में अहम भूमिका निभाई है।

ओशन डार्कनिंग का प्रभाव

- समुद्री पारिस्थितिकी और उत्पादकता: यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर अनेक प्रक्रियाओं जैसे- प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास आदि को प्रभावित करता है। साथ ही, इससे महासागरों की उत्पादकता में भी गिरावट आती है।
- मत्स्य उद्योग: ओशन डार्कनिंग की वजह से मछलियों का पर्यावास सिकुड़ रहा है, जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है और मछलियों की संख्या घटती है।
- जलवायु का विनियमन: महासागर में कार्बन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे जलवायु विनियमन प्रभावित होता है।



बिहार शहरी चुनावों में ई-वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस महीने के अंत में होने वाले आगामी नगर पालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल का उपयोग करके ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) सिस्टम लोगों को कंप्यूटर, वोटिंग मशीन (DREs) और स्मार्ट कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके वोट करने में सक्षम बनाएगा।

बिहार में होने वाली ई-वोटिंग की मुख्य विशेषताएं

- मोबाइल ऐप्लिकेशन: ई-वोटिंग प्रक्रिया में दो एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होगा (अर्थात् – “e-Voting SECBHR”)। इनमें एक ऐप C-DAC द्वारा और दूसरा बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
- सुरक्षा: इस सिस्टम में ब्लॉकचेन तकनीक, लाइवनेस डिटेक्शन, और चेहरे की पहचान (फेस मैच, लाइव स्कैन एवं तुलना) जैसी सुविधाएं शामिल हैं, ताकि वोटिंग प्रक्रिया सुरक्षित व वैध तरीके से हो।
- ऑडिट ट्रेल: जैसे EVM के साथ VVPAT होता है, वैसे ही यहां हर वोट को ट्रैक और जांचने के लिए ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

ई-वोटिंग का महत्व

- बेहतर पहुंच: ई-वोटिंग उन लोगों के लिए मतदान को आसान बनाती है, जो पारंपरिक वोटिंग में अक्सर बाधाओं का सामना करते हैं — जैसे कि प्रवासी मजदूर, दिव्यांगजन आदि।
- युवा और मोबाइल वोटर: ऑनलाइन वोटिंग तकनीक समझने वाले युवाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। यह पहली बार वोट डालने वालों के लिए मतदान आसान बनाती है और उनमें लंबे समय तक मतदान की आदत विकसित करने में मदद करती है।
- मतदाता संख्या में वृद्धि: ऑनलाइन वोटिंग से समय और मेहनत की बचत होती है, जिससे ज्यादा लोग वोट डाल पाते हैं। विशेषकर हाशिए पर मौजूद और लगातार यात्रा करने वाले लोग आसानी से मतदान कर सकते हैं।

ई-वोटिंग को लेकर चिंताएं

- ई-वोटिंग हैकिंग, गड़बड़ी और धोखाधड़ी के खतरे के प्रति सुभेद्य हो सकती है। घर से वोट डालने पर यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि मतदान गोपनीय और दबावमुक्त हुआ है या नहीं। इसके अलावा, इंटरनेट की सुविधा या डिजिटल जानकारी न होने पर कई नागरिक इससे वंचित भी रह सकते हैं।

निष्कर्ष

ई-वोटिंग को अपनाना चुनावी प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो मतदान को और अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाने का वादा करता है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल रूप से वंचित लोगों की भागीदारी और मतदाता पर दबाव जैसे मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाता है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास एवं समावेशिता बनी रहे।



महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा बनाने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया

यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप ‘स्कूली शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2024’ के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में उठाया गया है।

प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को, जो मराठी या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी।
- यदि प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ना चाहें, तो उन्हें हिंदी पढ़ने से छूट दी जा सकती है।

लि-भाषा फॉर्मूला क्या है?

- उत्पत्ति: इसे पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था, जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी।

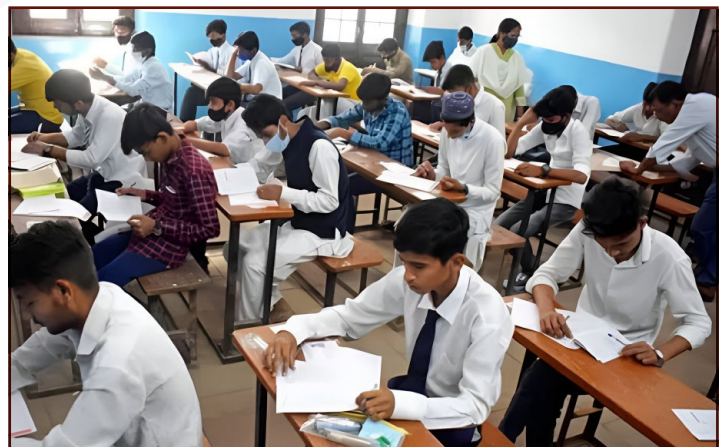
⊕ इसमें कहा गया था कि छात्रों को मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा, एक आधिकारिक भाषा, और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भी भाषा को थोपे बिना लि-भाषा फॉर्मूला (जिसमें कम-से-कम दो स्थानीय भाषाएं हों) को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें राज्यों, क्षेत्रों और बच्चों की पसंद का ध्यान रखा गया है।

⊕ इसमें यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक, और बेहतर हो तो कक्षा 8 या उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए।

लि-भाषा नीति की आवश्यकता क्यों है?

- संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है।
- सांस्कृतिक महत्व: यह बहुभाषावाद, बहुसंस्कृतिवाद, राष्ट्रीय एकता और युवा छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है।



लि-भाषा नीति को लागू करने में चुनौतियां

- राजनीतिकरण: बहुभाषी शिक्षा को कई बार स्थानीय भाषाओं की पहचान के लिए खतरा माना जाता है। उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र और कर्नाटक के मूल निवासियों द्वारा हिंदी का विरोध।
- विकल्प बनाम थोपना: भाषा सीखना थोपने की बजाय विकल्प होना चाहिए।
- प्राथमिक छात्रों पर अत्यधिक बोझ: पहले से ही भारत में कई बच्चे बुनियादी साक्षरता से जूझ रहे हैं। ऐसे में तीन भाषाएं जोड़ना उनके लिए शैक्षणिक दबाव बढ़ा सकता है।
- कार्यान्वयन की चुनौतियां: भाषाई रूप से विविध राज्यों (जैसे नागालैंड) और जनजातीय क्षेत्रों में इसे लागू करना कठिन है। कई राज्यों के पास शिक्षकों, प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है।

शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए 'परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (PGI) 2.0' जारी किया

PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन का समय मूल्यांकन करता है। इसके लिए यह यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+), नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS), पीएम-पोषण पोर्टल, प्रबंध (PRABANDH) पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल से जुटाए गए डेटा का उपयोग करता है।

PGI 2.0 के बारे में

- उत्पत्ति: PGI की शुरुआत 2017 में की गई थी, और बाद में इसे 2021 में PGI 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया गया।
- संरचना: PGI की संरचना में कुल 1000 अंकों का भारांक होता है, जिन्हें 73 संकेतकों (indicators) में बाँटा गया है। इन संकेतकों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा गया है:

- परिणाम (Outcome); तथा
- अभिशासन और प्रबंधन (Governance & Management)।

- इन श्रेणियों को आगे 6 क्षेत्रों (डोमेन) में बाँटा गया है:

- लर्निंग आउटकम्स (LO) – अधिगम परिणाम;
- एक्सेस (A) – पहुँच;
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ (IF);
- इक्विटी (E) – समानता;
- गवर्नेंस प्रोसेसेस (GP) – अभिशासन प्रक्रियाएँ; तथा
- टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (TET) – शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण।

- मूल्यांकन: PGI में प्रदर्शन का मूल्यांकन 1000 अंकों के आधार पर किया जाता है, और इसके अनुसार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड्स में रखा जाता है।

इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष चार ग्रेड (दक्ष, उत्कर्ष, अति-उत्तम व उत्तम) प्राप्त नहीं कर सका।
- शीर्ष प्रदर्शन: केवल चंडीगढ़ ने प्रचेस्टा-1 (Prachesta-1) ग्रेड हासिल किया।
- सबसे कमजोर प्रदर्शन: मेघालय एकमात्र राज्य है, जो दसवें ग्रेड (आकांक्षी-3/ Akanshi-3) में रहा।
- समग्र रुझान:
 - 2023-24 में 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर 2022-23 की तुलना में बेहतर रहे हैं।
 - जबकि 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक आदि में स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है।

प्राप्तांक (% में)	स्कोर सीमा	ग्रेड
91% से 100%	941-1000	दक्ष (Daksh)
81% से 90%	881-940	उत्कर्ष (Utkarsh)
71% से 80%	821-880	अति-उत्तम (Atti-Uttam)
61% से 70%	761-820	उत्तम (Uttam)
51% से 60%	701-760	प्रचेष्टा -1 (Prachesta-1)
41% से 50%	641-700	प्रचेष्टा -2 (Prachesta-2)
31% से 40%	581-640	प्रचेष्टा -3 (Prachesta-3)
21% से 30%	521-580	आकांक्षी -1 (Akanshi-1)
11% से 20%	461-520	आकांक्षी -2 (Akanshi-2)
10% तक	401-460	आकांक्षी -3 (Akanshi-3)



अन्य सुर्खियां



फ्रंट रनिंग

- हाल ही में SEBI ने IIFL सिन्योरिटीज के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों पर 'फ्रंट रनिंग' के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है।
- फ्रंट रनिंग के बारे में:
 - फ्रंट रनिंग एक गैर-कानूनी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति या ब्रोकर पहले से मिली गुप्त जानकारी का फायदा उठाकर किसी शेयर को खरीद या बेच लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्द ही कोई बड़ा लेन-देन होने वाला है, जिससे उस शेयर की कीमत प्रभावित होगी।
 - यह एक तरह से बाजार धोखाधड़ी है, क्योंकि इसमें शेयर की कीमतों में बदलाव की जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। इससे कुछ लोग अवैध तरीके से फायदा उठा लेते हैं।
 - उदाहरण: अगर कोई क्लाइंट बहुत बड़ी संख्या में शेयर खरीदने वाला है, तो ब्रोकर पहले खुद ही वही शेयर खरीद लेता है ताकि कीमत बढ़ने पर मुनाफा कमा सके।
 - ऐसा करने से लोगों का बाजार पर से भरोसा उठता है और निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है।



साहित्य अकादमी

- हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 और बाल पुरस्कार के लिए 24 विजेताओं के नाम की घोषणा की है।
- साहित्य अकादमी के बारे में
 - परिचय: यह भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है और देश की एकमात्र संस्था है जो 24 भारतीय भाषाओं (22 अनुसूचित भाषाएँ, अंग्रेज़ी और राजस्थानी) में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
 - स्थापना: इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
 - मंत्रालय: यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है।



अगरवुड

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि अगरवुड का वैश्विक व्यापार जंगली और संकटग्रस्त पेड़ों पर निर्भर है, जिससे इन पेड़ों के संरक्षण का खतरा पैदा हो गया है।

अगरवुड (औषध या गहू) के बारे में

- अगरवुड एक सुगंधित, रेजिनयुक्त लकड़ी है जो थाइमोलेसी फैमिली के एक्विलारिया और गायरिनोप्स प्रजातियों के पेड़ों से प्राप्त होती है।
- जब पेड़ का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है या वे फफूंद से संक्रमित होते हैं, तो वे प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में रेजिन का उत्पादन करते हैं, यही अगरवुड होता है।
- कहाँ पाया जाता है: यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से मिलता है। लिपुरा की राजधानी अगरतला का नाम भी अगरवुड से जुड़ा है।
- भारत में अगरवुड की एक्विलारिया खसियाना और एक्विलारिया मालाकेन्सिस प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- संरक्षण स्थिति:
 - यह CITES के परिशिष्ट II में शामिल है।
 - इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में भी सूचीबद्ध किया गया है।
 - एक्विलारिया मालाकेन्सिस को IUCN रेड लिस्ट में क्रीटीकली एंडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत ने CITES के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड (RST) में एक्विलारिया मालाकेन्सिस को शामिल होने से सफलतापूर्वक रोका है, जिससे व्यापार प्रतिबंधों में ढील मिली है।
- उपयोग: इसका उपयोग इत्र बनाने, पारंपरिक चिकित्सा आदि में होता है (प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, चीनी चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा में इसका उल्लेख मिलता है)।



ऑपरेशन सिंधु

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू किया।

ऑपरेशन सिंधु के बारे में:

- ईरान और आर्मेनिया की मदद से 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया।
- ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण, भारतीय नागरिकों को उत्तरी ईरान से नुर्दुज-अगराक सीमा मार्ग से होते हुए सड़क के रास्ते आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुँचाया गया।
- भारत के ईरान के दो अन्य पड़ोसी देशों - तुर्कमेनिस्तान और इराक के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जबकि ईरान के अन्य पड़ोसी देशों - तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ संबंध ऑपरेशन सिंधु के दौरान खराब हो गए थे।
- ईरान के एक अन्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन से भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।



माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी

हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकीलाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी के बारे में

- प्रकार: माउंट लेवोटोबी दो पास-पास स्थित स्तरीकृत ज्वालामुखियों (stratovolcanoes) — लेवोटोबी लाकी-लाकी (पुरुष) और लेवोटोबी पेरेंपुआन (महिला) से बना है।
- स्थान: यह इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर अवस्थित है।
- भौगोलिक अवस्थिति: यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है।



फास्टैग (FASTag)

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग याता को बाधा रहित बनाने के लिए FASTag वार्षिक पास लॉन्च किया है।

फास्टैग तकनीक के बारे में

- यह एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करके वाहन के चलते समय ही सीधे टोल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इसे वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। यह ग्राहक को सीधे उस खाते से टोल भुगतान करने की सुविधा देता है जो फास्टैग से जुड़ा होता है।
- विकास: इसे NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) कार्यक्रम के तहत विकसित किया है।
- NETC कार्यक्रम NPCI, NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), और IHMCL (इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) द्वारा शुरू किया गया है।



रिवर्स फ्लिपिंग

सेबी (SEBI) ने देश में स्टार्टअप IPO को बढ़ावा देने के लिए 'रिवर्स फ्लिपिंग' को प्रोत्साहित करने के मकसद से शेयर बाजार में कुछ नियमों को आसान किया है।

रिवर्स स्लीपिंग के बारे में:

- “रिवर्स फ्लिपिंग” उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें कोई स्टार्टअप, जो पहले किसी अन्य देश में पंजीकृत था, अब अपना मुख्य गंतव्य (मुख्यालय/ पता) वापस अपने देश में स्थानांतरित करता है।
- भारत में रिवर्स फ्लिपिंग का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि:
 - स्टार्टअप भारतीय शेयर बाजारों में लिस्ट होने की योजना बना रहे हैं,
 - भारत की आर्थिक नीतियाँ मजबूत हैं,
 - देश का स्थानीय बाजार लगातार बढ़ रहा है,
 - टैक्स व्यवस्था अनुकूल हो रही है,
 - निवेशकों की संख्या और उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है।



INS अर्नाला

हाल ही में INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

INS अर्नाला के बारे में

- नामकरण और महत्त्व: इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले अर्नाला के नाम पर रखा गया है। यह भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक शैल वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है।
- यह स्वदेशी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण को प्रदर्शित करता है, जो “क्रेता आधारित नौसेना” से “निर्माता आधारित नौसेना” में बदलाव का प्रतीक है।
- विशेषताएं: यह 77 मीटर लंबा है और भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसे डीजल इंजन-बॉटरजेट संयोजन से चलाया जाता है।
- क्षमताएं: यह जल के नीचे निगरानी और अवरोधन, खोज और बचाव मिशन और कम-तीव्रता वाले समुद्री अभियान (LIMO) को अंजाम देने में सक्षम है।

सुर्खियों में रहे स्थल



क्रोएशिया (राजधानी: ज़ाग्रेब)

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में क्रोएशिया की यात्रा की।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह दक्षिण-पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है।
- पड़ोसी देश: यह पांच देशों के साथ सीमाएं साझा करता है: इसके उत्तर में हंगरी, दक्षिण में मॉन्टेनेग्रो, पश्चिम में स्लोवेनिया, और पूर्व में सर्बिया तथा बोस्निया और हर्जगोविना हैं।
- क्रोएशिया की भूमि की एक संकीर्ण पट्टी एड्रियाटिक सागर के साथ लगती है।
- यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है।

भौगोलिक विशेषताएं

- प्रमुख पर्वत श्रृंखला: दीनारिक आल्प्स।
- प्रमुख नदियाँ: सावा और द्रवा।
- जलवायु: यहां जलवायु के दो प्रमुख प्रकार हैं-
 - महाद्वीपीय जलवायु: गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है।
 - आंशिक भूमध्यसागरीय जलवायु।



तुट्टि सुधार:

- न्यूज़ टुडे के 19 जून, 2025 के अंक में ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए शीर्षक से प्रकाशित मुख्य खबर में दी गई यह जानकारी गलत है कि, ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी।
- सही जानकारी है, ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी।



अहमदाबाद



बेंगलूर



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची